

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

मानसून का कहर: 5 लोगों की मौत

◆ दून में कार बहने से 2, अल्मोड़ा में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत

हमारे संवाददाता

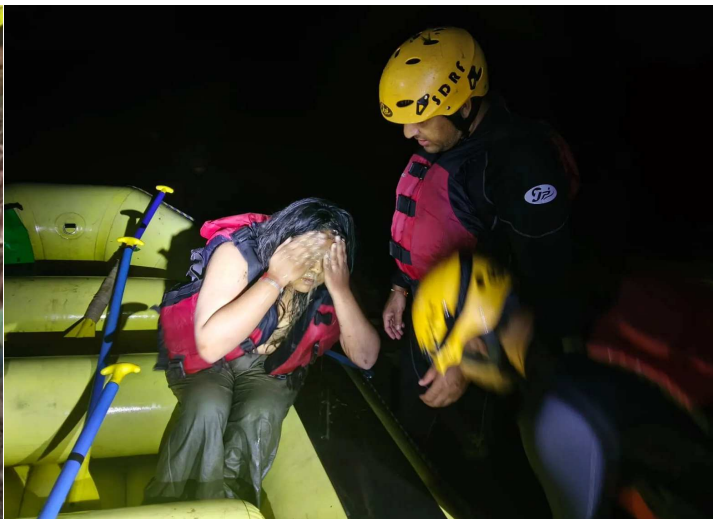
देहरादून। राज्य में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दून में बीती रात हुई बरसात के चलते जहां एक कार बहने से दो लोगों की मौत व एक घायल की सूचना है तो वहीं अल्मोड़ा में एक मकान के जमींदोज हो जाने पर वहां सो रहे तीन लोगों की मौत हो गयी। हालांकि दोनों स्थानों पर प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया लेकिन कुदरत का कहर अपना कहर ढहाने में कामयाब रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात प्रेमनगर क्षेत्र के लोअर कंडोली, पौधा सड़क मार्ग पर स्थित कंडोली पुल के पास क्रेटा वाहन तेज बरसाती बहाव में बह गया। घटना में एक युवक और युवती की मौत हो गई जबकि एक युवती घायल हुई है। एसडीआरएफ टीम डाकपत्थर को सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल सर्चिंग एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। उक्त क्रेटा वाहन में 1 युवक एवं 0 युवतियां सवार थे। एसडीआरएफ टीम द्वारा देर रात्रि में विषम परिस्थितियों



में सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर सहज पुत्री गुलशन बवेजा को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया तथा पुलिस के सुपुर्द किया गया। वहीं सर्चिंग के दौरान वाहन में सवार अक्षय पुत्र मुकेश, उम्र 20 वर्ष, निवासी जयपुर, राजस्थान एवं एक अन्य युवती का शव बरामद कर लिया गया। दोनों शवों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस के सुपुर्द किया गया

वही दूसरी ओर भारी बारिश के बीच



अल्मोड़ा जिले में मलबा घुसने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान प्रेमा देवी (42 वर्ष), पत्नी राजेन्द्र राम, कल्पना आर्या (19 वर्ष) पुत्री राजेन्द्र राम और मनीष कुमार (18 वर्ष) पुत्र राजेन्द्र राम के रूप में हुई। वहीं, 01 व्यक्ति गुलाब राम मकान

के बाहर स्थित कमरे में सो रहे थे, जो मकान ढहने के दौरान सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि आज सुबह करीब चार बजे जिला आपदा कंट्रोल रूम को 112 नंबर के माध्यम से सूचना मिली थी कि वड्यूडा गांव के एक मकान में मलबा घुस गया है और कुछ लोग उसके अंदर दबे हुए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत-बचाव की टीमों मौके के लिए रवाना की गई।

जिला प्रबंधन अधिकारी ने बताया मकान के एक हिस्से में परिवार के बुजुर्ग मौजूद थे, जो सुरक्षित बच गए। वहीं बगल के कमरे में तीन लोग सो रहे थे। इनमें परिवार की बहू, उनका बेटा और बेटी शामिल थे।

पीछे की तरफ से आया भारी मलबा दीवार को तोड़ते हुए मकान के अंदर घुस गया और तीनों लोग मलबे में दब गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई। प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकाला। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। हादसे के बाद मौके पर एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और प्रशासन की टीमों मौजूद रहीं।

सीओ रानीखेत, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य की निगरानी की। दो एंबुलेंस भी मौके पर भेजी गई थीं। उन्होंने बताया कि रास्ते में मलबा आने के बावजूद प्रशासन की ओर से राहत-बचाव टीमों को समय पर मौके तक पहुंचाया गया।

राहुल गांधी पर मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस का सचिवालय कूच, गिरफ्तारी

संवाददाता

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किये जाने के विरोध में कांग्रेस का सचिवालय कूच के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण की घटना के बाद मामला गर्मा गया। जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के थानों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गयी। इसी के चलते आज कांग्रेस का सचिवालय कूच था। सुबह ही कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया। कांग्रेस कार्यकर्ता जब सचिवालय

के करीब पहुंचे तो पुलिस ने बैरकडिंग लगाकर उनको रोक दिया जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गये। उनका कहना था कि 10 अगस्त को रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण को लेकर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे अनुसूचित जाति-जनजाति विरोधी करार दिया साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को ध्यान भटकाने और आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए कहा कि पार्टी इसका लोतांत्रिक और कानूनी तरीके साथ मुंहतोड़ जवाब देगी।

उनका कहना था कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में दलितों के साथ हो रहे अन्याय, अपमान और भेदभाव का जो सवाल उठाया उसे सही साबित करने में भाजपा आरएसएस ने 24 घंटे भी नहीं



लगाये। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण के नाम पर किये गये छूआछूत और अपमान में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन उत्तराखण्ड की डबल इंजन सरकार ने आरोपियों की बजाये न्याय की मांग कर रहे नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ही अगले दिन एफआईआर दर्ज करा दी।

उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा व आरएसएस इस गलतफहमी में न रहें कि केस के डर से राहुल गांधी या कांग्रेस पीछे हट जाएंगे। एफआईआर कर भाजपा की डरपोक सरकार ने अपना चेहरा दिखा दिया है। यह भाजपा के अहंकार व तानाशाही की पराकाष्ठा है। जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन पहुंचाया।

दून वैली मेल

संपादकीय

अब महामारी का खतरा

नेपाल की नदियां इन दिनों सिर्फ पानी नहीं बहा रहीं, वह एक ऐसी त्रासदी की गवाही दे रही हैं जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल है। पहाड़ टूटे, बस्तियां उजड़ीं, सड़कें बह गईं और सैकड़ों परिवार अपने लोगों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। बाढ़ का पानी उतरने के साथ तबाही का दूसरा चेहरा सामने आ रहा है, नदियों के किनारे और मलबे में पड़े शव, भरते हुए शवगृह और अपनों की पहचान के लिए भटकते परिवार। यह महज प्राकृतिक आपदा नहीं रह गई है। अब यह मानवीय और स्वास्थ्य आपदा में बदलने का खतरा पैदा कर रही है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद सैकड़ों शव बरामद किए जा चुके हैं और हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में शवों की पहचान तक मुश्किल हो रही है। शवगृहों पर दबाव बढ़ रहा है और कुछ स्थानों पर अस्थायी दफन की व्यवस्था तक करनी पड़ रही है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहत अभियान केवल जीवित बचे लोगों की तलाश और मलबा हटाने तक सीमित रहेगा? या सरकारें उस स्वास्थ्य संकट की तैयारी भी करेंगी जो आपदा के बाद तेजी से सामने आ सकता है? बाढ़ के बाद दूषित पानी, खराब स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बाधित होने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हजारों विस्थापित लोगों के सामने रहने, भोजन और साफ पानी की समस्या है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी तत्काल सहायता की जरूरत है। यही वह मोड़ है जहां प्रशासनिक संवेदनशीलता और वैज्ञानिक तैयारी दोनों की परीक्षा होती है। शव किसी आंकड़े का हिस्सा नहीं होते। हर शव के पीछे एक परिवार होता है, एक कहानी होती है और किसी के लौट आने की उम्मीद होती है। इसलिए शवों का सम्मानजनक प्रबंधन, पहचान और अंतिम संस्कार केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, मानवीय जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राहत शिविरों और प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पानी, साफ-सफाई और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल पहुंचें। नेपाल की इस त्रासदी ने हिमालय की नाजुकता को एक बार फिर सामने ला दिया है। जिस हिमालय को लंबे समय से विकास की प्रयोगशाला बनाने की होड़ लगी है, वही हिमालय अब बार-बार चेतावनी दे रहा है। ग्लेशियरों की अस्थिरता, अचानक आने वाली बाढ़, अनियंत्रित निर्माण और जलवायु परिवर्तन के बदलते प्रभावों को अलग-अलग घटनाओं की तरह देखने की भूल अब भारी पड़ सकती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आपदा समाप्त होने के बाद भी उसका खतरा समाप्त नहीं होता। पानी उतर जाता है, लेकिन बीमारी, विस्थापन, बेरोजगारी, मानसिक आघात और भूख का संकट लंबे समय तक बना रह सकता है। नेपाल में हजारों परिवारों के लिए आने वाले दिन इसी कठिन परीक्षा के होंगे। इस त्रासदी से भारत को भी सीखना होगा। हिमालय राजनीतिक सीमाओं से बंटा हो सकता है, लेकिन उसकी नदियां और पारिस्थितिकी सीमाओं को नहीं मानतीं। नेपाल में जो हुआ, उसका असर नीचे की ओर बसे भारतीय क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत और नेपाल के बीच केवल आपदा के समय राहत सहयोग नहीं, बल्कि साझा हिमालयी आपदा प्रबंधन तंत्र की जरूरत है। आज जरूरत संवेदना के साथ विज्ञान की है। राहत के साथ दीर्घकालीन पुनर्वास की है। शवों की तलाश के साथ जीवित बचे लोगों के भविष्य की चिंता की है। नेपाल को इस समय सिर्फ आर्थिक मदद नहीं चाहिए, उसे समन्वित मानवीय सहायता, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, संचार और वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन की जरूरत है और दुनिया को यह समझना होगा कि हिमालय की चेतावनी को अनसुना करने की कीमत केवल नेपाल नहीं चुका रहा। यह पूरी हिमालयी पट्टी के लिए चेतावनी है। नदियों में बहती लाशें सिर्फ एक देश की त्रासदी नहीं हैं। वह उस विकास माडल पर सवाल हैं, जो प्रकृति की सहनशीलता को अंतहीन मान बैठा है। आज नेपाल रो रहा है और कल यह सवाल हमारे दरवाजे पर भी खड़ा हो सकता है।

खटीमा के शहीदों को परिषद ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये

संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने खटीमा में हुए शहीदो को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।
आज यहां उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य प्राप्ति के लिए खटीमा में शहीद हुए शहीदों को कचहरी परिसर सहित स्मारक में याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार वह प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रभात डंडरियाल ने कहा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि राज्य का चौमुखी विकास हो राज्य प्रगति की ओर अग्रसर रहे तथा खुशहाल रहे। खटीमा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात डंडरियाल, संरक्षक बलेश बवानिया, अनंत आकाश, अमित परमार, विकास रावत, जगमोहन रावत, रेखा शर्मा, परमिला रावत, पंकज, कल्पेश्वरी नेगी व सुभागा फरसवान चनदरा, सुंदरियाल आदि शामिल रहे।



हादसे की ‘तारीख’ का इंतजार

संवाददाता
देहरादून। पहाड़ में बारिश कहर बरपा रही है और इसी बारिश के बीच अल्मोड़ा के लोधिया में सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत बच्चों के सिर पर सवाल बनकर खड़ी है। नगर से महज तीन किलोमीटर दूर स्थित राजकीय इंटर कालेज लोधिया का भवन ऐसी हालत में है कि किसी भी समय गंभीर हादसे की आशंका बनी हुई है। विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन सोमवार को बारिश और भवन की खस्ताहाली के चलते सिर्फ 25 बच्चे ही स्कूल पहुंचे। यह आंकड़ा सिर्फ उपस्थिति रजिस्टर का नंबर नहीं है। यह उस डर की गवाही है, जो अभिभावकों के मन में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बैठ चुका है।
सबसे चुभने वाली बात यह है कि भवन की हालत अचानक खराब नहीं हुई। विद्यालय और अभिभावक लंबे समय से इसे दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं। शिकायतें हुईं, आवार्जे उठीं, लेकिन सरकारी तंत्र की नींद नहीं टूटी। अब लगातार बारिश ने जर्जर भवन को और जोखिम भरा बना दिया है। आखिर जिम्मेदार विभाग को किस चीज का इंतजार है? क्या किसी बच्चे के घायल होने का? क्या भवन का कोई हिस्सा गिरने का? या फिर उस दिन का, जब प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव की तस्वीरें जारी करे?हादसा होने के बाद कार्रवाई करना प्रशासनिक सफलता नहीं, व्यवस्था की विफलता होगी। जब भवन की स्थिति को लेकर स्कूल और

अभिभावक पहले से चेतावनी दे रहे हैं तो फिर समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई? बारिश शुरू होने के बाद भी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सोमवार को स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 25 रह गई। बाकी बच्चे कहाँ हैं? जवाब किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि अभिभावकों के

◆अल्मोड़ा में जर्जर स्कूल की छत के नीचे भविष्य गढ़ने को मजबूर 200 मासूम
◆अल्मोड़ा के स्कूल का जर्जर भवन कभी भी बन सकता है हादसे का सबब
◆200 से ज्यादा छात्र-छात्राएं, बारिश के बीच आज सिर्फ 25 पहुंचे स्कूल
◆वर्षों से स्कूल के मरम्मत की गुहार, विभाग आज दिन तक है इससे बेखबर
◆केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा का क्षेत्र, राज्य मंत्री कुंदन लटवाल का भी गृह क्षेत्र, फिर भी बच्चों की सुरक्षा पर क्यों खामोशी

डर में छिपा है, जिस स्कूल की इमारत देखकर माता-पिता अपने बच्चों को घर पर रोकने को मजबूर हो जाएं, वहां शिक्षा व्यवस्था की सफलता के दावे कितने खोखले हैं, यह समझना मुश्किल नहीं। स्कूल बच्चों के लिए ज्ञान का मंदिर होना चाहिए, लेकिन लोधिया में वही भवन बच्चों और अभिभावकों के लिए चिंता का कारण बन गया है।
लोधिया कोई ऐसा दूरदराज का इलाका नहीं है जहां प्रशासन की नजर पहुंचना मुश्किल हो। यह अल्मोड़ा नगर से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर है और राजनीतिक सवाल इससे भी बड़ा है। यह

क्षेत्र केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा से जुड़ा हुआ है। हाल में राज्य मंत्री बने कुंदन लटवाल का घर भी इसी क्षेत्र में बताया जाता है। तो फिर सवाल स्वाभाविक है कि जब सत्ता के इतने करीब होने के बावजूद एक सरकारी स्कूल की इमारत वर्षों से बदहाल है, तब पहाड़ के दूरस्थ गांवों के सरकारी स्कूलों की हालत कौन पूछेगा? क्या जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं में बच्चों की सुरक्षा शामिल है? अगर शामिल है तो लोधिया कालेज अब तक क्यों नहीं सुधरा?
उत्तराखंड में सरकारी भवनों की बदहाली कोई नई कहानी नहीं है। हर बरसात में स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन और दूसरी सरकारी इमारतें अपनी जर्जर हालत का सच सामने लाती हैं। लोधिया कालेज भी उसी व्यवस्था की तस्वीर बन गया है, जहां शिकायत पहले होती है और कार्रवाई हादसे के बाद। यह सवाल सिर्फ शिक्षा विभाग से नहीं है। प्रशासन, शिक्षा महकमा और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सभी को जवाब देना होगा कि जब भवन को लेकर लगातार मांग उठ रही थी तो अब तक क्या किया गया? क्या भवन का तकनीकी निरीक्षण हुआ? क्या इसे सुरक्षित घोषित किया गया है? अगर सुरक्षित है तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से क्यों डर रहे हैं? अगर असुरक्षित है तो स्कूल में कक्षाएं क्यों चल रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर बारिश के बीच भवन गिर गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

राष्ट्रीय फलक पर गूंजा ‘शुद्धिकरण’ विवाद

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2०27 की तैयारियां तेज होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव भी लगातार धार पकड़ रहा है। भाजपा ने कांग्रेस पर मुद्दाविहीन राजनीति और तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए हमला तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए वह धार्मिक, जातीय और भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर राजनीतिक जमीन तलाश रही है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस को प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा और पर्यटन जैसे सवालों पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। इसके बजाय पार्टी ऐसे मुद्दों को तूल दे रही है, जिनसे समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा हो सकता है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद सामने आए कथित शुद्धिकरण विवाद को लेकर कांग्रेस की आक्रामकता को भी भाजपा इसी रणनीति का हिस्सा बता रही है। भाजपा का कहना है कि स्थानीय घटना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है।

आगे कर रही है, जबकि प्रदेश के विकास से जुड़े सवालों पर उसका एजेंडा स्पष्ट नहीं है। भाजपा इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दे रही है। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड की जनता विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाएं चाहती है, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक विमर्श लगातार ऐसे मुद्दों की ओर जा रहा है जो भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। भाजपा की रणनीति भी साफ दिखाई दे रही है। वह कांग्रेस को

◆भाजपा का हमला, जनता के सवालों से बचने के लिए कांग्रेस धार्मिक और जातीय मुद्दों का सहारा
◆संसद से लेकर प्रदेश के गलियारों तक गरमाई राजनीति, 2०27 की लड़ाई के साफ हुए शुरुआती संकेत

विकास के सवाल पर घेरने के साथ-साथ उसके राजनीतिक मुद्दों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है।
कांग्रेस भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सामाजिक सम्मान, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को तुष्टिकरण कहना भाजपा की राजनीतिक रणनीति है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बजाय विपक्ष पर आरोप लगाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रही है। पार्टी का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और आपदा

जैसे सवाल आज भी जनता के सामने हैं और वह इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएगी। यानी दोनों दलों ने अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है।
उत्तराखंड में 2०27 का विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई के साथ-साथ नैरेटिव की लड़ाई भी बनने जा रहा है। भाजपा जहां कांग्रेस को तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा को बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और जनसमस्याओं पर जवाबदेह बनाने की तैयारी में है। इस राजनीतिक जंग में दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे जनता के सामने अपना एजेंडा कितनी मजबूती से रख पाते हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि उसे भाजपा के मजबूत संगठन और सत्ता विरोधी भावनाओं के बीच अपनी चुनावी जमीन तैयार करनी है। वहीं भाजपा के सामने सत्ता में वापसी की हैट्रिक का लक्ष्य है, जिसके लिए उसे सरकार के कामकाज को लेकर जनता के सवालों का जवाब भी देना होगा।
आने वाले महीनों में हल्द्वानी का शुद्धिकरण विवाद, धार्मिक पहचान, सामाजिक सम्मान और तुष्टिकरण जैसे मुद्दे उत्तराखंड की राजनीति में और उछल सकते हैं। चुनावी माहौल बनने के साथ राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों को अपने-अपने

पलायन रोकने को देवभूमि एकता मंच करेगा पहल: बिष्ट

रुद्रपुर(आरएनएस)। जवाहर नगर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामलाल वर्मा खेल मैदान में देवभूमि एकता मंच की सभा आयोजित हुई। सभा में संगठन के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष खेम सिंह बिष्ट ने कहा कि देवभूमि में निवास करने वाले पर्वतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए मंच पूरी मजबूती से कार्य करेगा। पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए भी ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि एकता मंच को पूरी तरह राजनीति से दूर रखा जाएगा। संगठन का उद्देश्य जरूरतमंद और शोषित लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें हरसंभव सहयोग और सहारा देना है। पर्वतीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता को संरक्षित करना भी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. बीडी जोशी, डॉ. कुंदन सिंह माहोड़ी, संरक्षक नारायण सिंह बिष्ट, विनोद कोरंगा, कार्यक्रम अध्यक्ष गोविंद सिंह सिजवाली ने संगठन की एकता और मजबूती के लिए सदस्यों से निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान तेज करने पर जोर दिया। इस दौरान देवभूमि एकता मंच के सचिव कुंदन सिंह नेगी, गुड्डु तिवारी, जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्य, डॉ. तेज सिंह बिष्ट, धन सिंह कोरंगा, कोषाध्यक्ष नारायण सिंह कोरंगा, मोहन सिंह दानू, बीसी कांडपाल, खुशाल सिंह कोरंगा, बहादुर सिंह नेगी, दीपक भट्ट, खजान सिंह, ईश्वर सिंह दानू आदि रहे।

आंतरिक मूल्यांकन से जुड़ी लापरवाही की जांच को उच्चस्तरीय समिति गठित

नैनीताल(आरएनएस)। कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने प्रेसवार्ता कर बताया कि भू-विज्ञान विभाग की दिल्ली निवासी छात्रा के आंतरिक मूल्यांकन अंकों की लापरवाही के मामले में अंकतालिका संशोधित कर उसे उपाधि दे दी गई है। छात्रा की ओर से फरवरी 2023 की अंतिम तिथि के बाद असाइनमेंट जमा करने और विभाग ने बिना अनुमति और अभिलेखों के अंक भेजने के दावे किए गए। मई 2023 में परिणाम आने के बाद यह मामला लंबे समय तक दबा रहा और समाधान पखवाड़े में भी प्रस्तुत नहीं हुआ। जुलाई 2026 में छात्रा के कुलपति से मिलने के बाद दस्तावेजों की जांच हुई, जिसके आधार पर 30 जुलाई को परीक्षा समिति की प्रत्याशा में अंकतालिका संशोधित की गई। विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अधिकांश घटनाएं पूर्व प्रशासन के कार्यकाल की हैं। इस प्रक्रियागत चूक की जिम्मेदारी तय करने के लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति से उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।

छह सितंबर को होगी सवर्ण समाज की बड़ी बैठक

हरिद्वार(आरएनएस)। बिल्केश्वर मंदिर प्रांगण में सवर्ण समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी छह सितंबर को बहादुराबाद में होने वाली बैठक में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और उसे सफल बनाने पर चर्चा की गई। पं. अधीर कौशिक ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में भय का माहौल है और युवा चिंतित हैं। सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। उन्होंने छह सितंबर को बहादुराबाद में होने वाली बैठक में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। पंडित पवन कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आगामी बैठक में समाज से जुड़े हजारों लोग शामिल होंगे। कार्तिक गिरी और आचार्य विष्णु पंडित ने कहा कि लोगों को जागरूक कर एकजुट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियम जनहित में नहीं हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर ऋषि शर्मा, बालकृष्ण शास्त्री, डॉ. दिनेश बाली, सुशील शुक्ला, आदित्य, सचिन पैन्थली, शीतल उपाध्याय, निशाकांत शुक्ला, अनिल शर्मा, राखी सजवान और मनुश्री आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रपति भवन पहुंचकर अभिभूत छात्र

विकासनगर(आरएनएस)। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कालसी के छात्र-छात्राओं के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का शैक्षणिक भ्रमण यादगार और प्रेरणादायी रहा। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रपति भवन की भव्यता और देश की संवैधानिक व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर मिला। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट भी की। राष्ट्रपति भवन भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने भवन की ऐतिहासिक विरासत, भव्य स्थापत्य कला और राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन परिसर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों और संग्रहालय का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने वहां देश के गौरवशाली इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ी जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति से भेंट का अवसर विद्यार्थियों के लिए विशेष आकर्षण रहा। राष्ट्रपति को अपने बीच देखकर विद्यार्थियों में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। विद्यार्थियों ने इस अनुभव को जीवन का महत्वपूर्ण और यादगार अवसर बताते हुए कहा कि इस प्रकार के भ्रमण से उन्हें देश की व्यवस्था और विरासत को समझने का व्यावहारिक अवसर मिलता है। प्रधानाचार्य रजनीश सिर्रोहा, शिक्षक हेमचंद्र ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को देश के इतिहास, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है।

उत्तराखंड की राजनीति का ‘गोल्डन रूल’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामाजिक बुनावट रही है। पहाड़ से मैदान तक समाज अनेक जातियों, समुदायों और वर्गों में बंटा होने के बावजूद चुनावी राजनीति में उत्तराखंड की जनता ने लंबे समय तक जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर स्थायी खांचे स्वीकार नहीं किए। यहां मतदाता की अपनी राजनीतिक समझ रही है और वह समय-समय पर सरकारों और नेताओं को उनके कामकाज के आधार पर परखता रहा है।

उत्तराखंड का गठन ही लंबे जनआंदोलन की उस भावना से हुआ था, जिसमें क्षेत्रीय अस्मिता, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ के विकास को केंद्रीय मुद्दा बनाया गया। आंदोलन के दौर में जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग एक साझा मांग के साथ सड़कों पर उतरे। यही सामाजिक चेतना आज भी प्रदेश की राजनीति की बुनियाद में दिखाई देती है।

उत्तराखंड की राजनीति को केवल पहाड़ और मैदान के बीच विभाजन के नजरिए से भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे मैदानी जिलों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं तो सीमांत और पर्वतीय जिलों के अपने सवाल। इसके बावजूद चुनावों में मतदाता कई बार स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की छवि को पार्टी के पारंपरिक समीकरणों पर भारी कर देता है। यही कारण है कि उत्तराखंड में किसी एक जाति या समुदाय को स्थायी वोट बैंक मान लेना राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं रहा है।

उत्तराखंड धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश है। चारधाम, प्रमुख शक्तिपीठ और अनेक स्थानीय देव परंपराएं यहां की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन धार्मिक आस्था और चुनावी राजनीति को एक ही तराजू में रखना हमेशा सही नहीं रहा। प्रदेश

तीन दिन में परीक्षाफल घोषित करेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय

नैनीताल(आरएनएस)। स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित करने की मांग को लेकर कुमाऊं विवि नैनीताल के प्रशासनिक भवन में जारी छात्रनेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल विवि प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। शनिवार शाम से हड़ताल पर बैठे छात्रों से वार्ता के लिए विवि के अधिकारी पहुंचे। कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन, संकायाध्यक्ष कला, विज्ञान, बायोमेडिकल साइंस, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कुलानुशासक एवं उप परीक्षा नियंत्रक और आंदोलित विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई। आश्चर्य किया गया कि विवि की ओर से स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफल तीन दिन के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद जिन विद्यार्थियों के आंतरिक एवं प्रायोगिक मूल्यांकन के अंक छूट गए हैं, उनके लिए निश्चित समयावधि के तहत विलंब शुल्क के साथ परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए सभी परिसरों / संबद्ध महाविद्यालयों को सूचना भेजी जाएगी। उन्हें निर्धारित समयावधि में अंक विवि को भेजने होंगे।

का मतदाता धार्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने रोजमर्रा के सवालों को भूल जाता है। सड़क टूटने पर सड़क चाहिए, अस्पताल में डाक्टर चाहिए, स्कूल में शिक्षक चाहिए और



◆उत्तराखंड की सियासत में नहीं चलता जाति-धर्म का गणित
◆पहाड़ की जनता ने विकास, ईमानदारी, जनहित को तरजीह दी
◆पहचान की राजनीति से ज्यादा मुद्दों की राजनीति रही है हावी

युवाओं को रोजगार चाहिए। पहाड़ में पलायन रोकना है तो स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसर चाहिए। आस्था अपनी जगह है और शासन का सवाल अपनी जगह। उत्तराखंड में जातीय पहचानें मौजूद हैं और राजनीतिक दल चुनावों में सामाजिक समीकरणों का आकलन भी करते हैं। मगर यहां जाति को चुनाव जीतने की गारंटी मान लेना जोखिम भरा रहा है। एक ही जाति या समुदाय के मतदाता अलग-अलग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। इसका कारण उत्तराखंड की सामाजिक संरचना और राजनीतिक चेतना दोनों में देखा जा सकता है। छोटे राज्य में स्थानीय रिश्ते, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, क्षेत्रीय जुड़ाव और उसके कामकाज का असर कई बार व्यापक जातीय समीकरणों पर भारी पड़ता है।

आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी

महिला कोतवाली पुलिस ने गांव-गांव पहुंचकर जाना वरिष्ठ नागरिकों का हालचाल

अल्मोड़ा(आरएनएस)। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी नियमित कुशलक्षेम जानने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन भल छौ’ के तहत महिला कोतवाली पुलिस ने गांवों में पहुंचकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। पुलिस टीम ने उनकी समस्याएं सुनीं, हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया और साइबर अपराधों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके के निर्देश पर जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले एकल बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों का विवरण दर्ज कर समय-समय पर उनसे मुलाकात करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला कोतवाली जानकी भण्डारी के नेतृत्व में महिला हेड कांस्टेबल कविता बिष्ट और महिला कांस्टेबल तुलसी गोस्वामी ने विभिन्न गांवों में पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। पुलिस टीम ने वरिष्ठ नागरिकों से उनकी दैनिक जरूरतों, स्वास्थ्य और

चुनौती यही होगी कि वह जनता को किस मुद्दे पर अपने साथ जोड़ते हैं। क्या चुनाव बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और आपदा प्रबंधन पर होगा या फिर जाति, धर्म और पहचान के भावनात्मक मुद्दे चुनावी विमर्श पर हावी होंगे? उत्तराखंड का मतदाता राजनीतिक दलों को यह संदेश देता रहा है कि उसे केवल भावनाओं से नहीं, परिणामों से मतलब है। सत्ता में बैठी सरकार से वह सवाल करता है और विपक्ष से भी विकल्प की स्पष्टता मांगता है।

उत्तराखंड की सामाजिक एकता को सबसे बड़ी चुनौती तब मिलती है जब राजनीतिक लाभ के लिए समाज को छोटे-छोटे खांचों में बांटने का प्रयास होता है। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण अल्पकाल में चुनावी लाभ दे सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करता है। उत्तराखंड की जनता ने राज्य आंदोलन से लेकर आज तक कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं। सरकारें बदलीं, चेहरे बदले और चुनावी मुद्दे बदले, लेकिन जनता की मूल आकांक्षाएं बहुत हद तक वही हैं। सम्मान के साथ रोजगार, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य, सुरक्षित सड़कें, मजबूत गांव और पलायन से मुक्ति।

इसलिए 2027 की चुनावी लड़ाई में भी राजनीतिक दलों के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि किस जाति या समुदाय को कैसे साधा जाए। बड़ा सवाल यह होगा कि क्या उत्तराखंड की जनता को विकास और जनहित का भरोसेमंद एजेंडा दिया जा सकता है? उत्तराखंड की असली पहचान किसी जाति, धर्म या वर्ग की राजनीति नहीं, बल्कि साझा पहाड़ी चेतना है। यहां मतदाता को बांटने की कोशिश भले हो सकती है, लेकिन उसे स्थायी खांचे में कैद करना आसान नहीं। सियासत चाहे जितने समीकरण बनाए, आखिर में फैसला उत्तराखंड की जनता अपने मुद्दों और अपनी समझ से ही करेगी।

सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही उन्हें थाना संपर्क नंबर और डायल-112 हेलपलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आपात स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अथवा अन्य आवश्यकता होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अभियान के दौरान पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों, नशे के दुष्प्रभाव, नए आपराधिक कानून, गैर शक्ति एप, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया। इसके अलावा डायल-112, साइबर हेलपलाइन-1930, महिला हेलपलाइन-1090, चाइल्ड हेलपलाइन-1098 और आपदा हेलपलाइन-1070 के उपयोग और महत्व की जानकारी भी दी गई। अपने घर पर पुलिस टीम को पहुंचकर कुशलक्षेम पूछते और सहायता का आश्वासन देते देख वरिष्ठ नागरिकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने महिला कोतवाली पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस की नियमित मौजूदगी से उनमें सुरक्षा का विश्वास और मजबूत हुआ है।

मेकअप के दौरान की गई ये गलतियां बिगाड़ सकती हैं खूबसूरती

चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दमकती और निखरी त्वचा के लिए घरेलू नुस्खों से लेकर महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट तक का इस्तेमाल करते हैं। बात कहीं जाने की हो या किसी पार्टी का हिस्सा बनने की, मेकअप करना जरूरी हो जाता है। मेकअप त्वचा खूबसूरत बनती है और कॉन्फिडेंस झलकता है। हालांकि, अगर ठीक तरह से मेकअप न किया जाए तो स्किन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दरअसल, मेकअप में इस्तेमाल किए जाने वाले हानिकारक केमिकल्स स्किन पर साइड इफेक्ट्स छोड़ सकते हैं। इसलिए मेकअप के दौरान 5 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए...

गंदा मेकअप ब्रश यूज करना

मेकअप के बाद अगर मेकअप ब्रश और स्पॉन्ज को सही तरह से साफ न किया जाए तो स्किन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक इनमें प्रोडक्ट लगे रहने से कीटाणु जनन लगते हैं, जो स्किन सेल्स तक पहुंचते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसलिए जब-जब मेकअप ब्रश और स्पॉन्ज का इस्तेमाल करें, उन्हें वॉश जरूर करें।

स्किन मॉइस्चराइज न करना

मेकअप से पहले त्वचा को मॉइस्चराइज करना चाहिए. इससे मेकअप काफी समय तक चेहरे पर बना रहता है. मॉइस्चराइज करने से त्वचा पर एक लेयर बन जाती है, जिससे मेकअप प्रोडक्ट त्वचा को नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर मेकअप से पहले त्वचा को मॉइस्चराइज न किया जाए तो इससे कई तरह की स्किन समस्याएं हो सकती हैं.

मेकअप रिमूव न करना

कई बार मेकअप हटाने के लिए सीधे फेश वॉश करना गलत होता है. इससे मेकअप प्रोडक्ट स्किन पर लगा रहता है और नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए मेकअप को सही तरह से रिमाव करना चाहिए. इसके लिए रिमूवर का इस्तेमाल करना चाहिए. किसी ऑयली मॉइस्चराइज को लगाकर भी मेकअप को हटा सकते हैं. इसके बाद ही फेश वॉश करें, जिसससे त्वचा की गहराई तक मेकअप साफ हो जाए.

हैवी फाउंडेशन का इस्तेमाल

आजकल कई वर्कप्लेस पर मेकअप की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप रोजाना हैवी फाउंडेशन का यूज करती हैं तो इससे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।

सोने से पहले मेकअप न हटाना

रात में स्किन को हील होने का वक्त मिलता है. इस दौरान त्वचा किसी भी चीज को गहराई से सोख लेती है. अगर आपके चेहरे पर मेकअप लगा है तो इससे स्किन एलर्जी, त्वचा का बेजान हो जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए सोने से पहले मेकअप रिमूव करना कभी न भूलें.

बरसात में इस प्रकार बचें पेट की परेशानियों से

बरसात का मौसम अब पूरी तरह शुरू हो चुका है ऐसे में तरह-तरह की बीमारियां भी लगती हैं। बरसात के मौसम में अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है।

दअसल, बरसात में वातावरण में नमी काफी बढ़ जाती है जिससे बैक्टीरिया के पनपने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। पेट में इंफेक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार गलत खानपान की वजह से तो कई बार सफ़ाई से नहीं रहने की वजह ये पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। इंफेक्शन हो जाने से बार-बार मोशन होना, कमजोरी होना, उल्टी होना और कभी-कभी बुखार होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

अगर आपका पेट खराब हो गया है और आप दवाई नहीं खाना चाहते तो इस प्रकार के रेलू उपाय करें।

पेट खराब होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। आप फलों का जूस और सब्जियों का रस भी ले सकते हैं। बेहतर होगा अगर पानी में लवण मिला हो। आप चाहें तो नींबू पानी, नमक-चीनी का गोल या फिर नारियल पानी ले सकते हैं। गाजर का जूस भी ऐसे समय में काफी फायदेमंद होता है।

अदरक का इस्तेमाल काफी कारगर होता है। इसमें एंटीफंगल और एंटी-बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जो पेट दर्द में राहत देता है। एक चम्मच अदरक पाउडर को दूध में मिलाकर पीने से आराम मिलता है। पेट दर्द में दही का इस्तेमाल काफी फायदेमंद रहता है। दही में मौजूद बैक्टीरिया संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिससे पेट जल्दी ठीक होता है। साथ ही ये पेट को ठंडा भी रखता है।

अगर आप बार-बार हो रहे मोशन से परेशान हो चुके हैं तो केले का इस्तेमाल आपको राहत देगा। इसमें मौजूद पेक्टिन पेट को बांधने का काम करता है। इसमें मौजूद पोटाशियम की उच्च मात्रा भी शरीर के लिए फायदेमंद होती है। अगर आपको लगातार दस्त हो रहे हों तो एक चम्मच जीरा चबा लें। जीरा चबाकर पानी पी लेने से दस्त बहुत जल्दी रुक जाते हैं।

घने और मुलायम बालों के लिए एक बार ट्राई कीजिए हेयर डिटॉक्स!

अच्छी सेहत के लिए जिस तरह से खानपान के साथ शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से घने और लंबे बालों के लिए सर्फ शैंपू, कंडीशनर और ऑयलिंग ही नहीं बल्कि आपको हेयर डिटॉक्स करने की भी जरूरत होती है। कई बार शैंपू से स्कैल्प और जड़ों में जमी धूल मिट्टी साफ नहीं होती है। इस वजह से आपको हेयर फॉल, ड्राई हेयर, हेयर ग्रोथ से जुड़ी परेशानी होने लगती है। ऐसे में आप हेयर डिटॉक्स करके इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, आईए जानते हैं घर में हेयर डिटॉक्स करने का तरीका क्या है

हेयर डिटॉक्स के फायदे

1। प्रदूषण के चलते स्कैल्प पर गंदगी जमा हो जाती है, जिस वजह से आपके बालों का ग्रोथ रुक जाता है। हेयर डिटॉक्स की मदद से स्कैल्प की सफाई होगी स्कैल्प में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा और बाल लंबे और घने होंगे।

2।प्रदूषण और ठीक से सफाई न करने की वजह से बालों की जड़ों में गंदगी जमा होने लगती है, जो कई बार रेगुलर शैंपू से साफ नहीं हो पाता है। इस वजह से बाल जड़ से कमजोर होने लगते हैं और हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। ऐसे में हेयर डिटॉक्स काफी फायदा पहुंचा सकता है।

3। प्रदूषण और धूल मिट्टी के संपर्क में

भूलकर भी इन 5 चीजों को न करें माइक्रोवेव, होगा भारी नुकसान

यदि आपका नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जो समय बचाने के लिए हर छोटी-बड़ी चीज के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। व्यक्ति आलसी हो या बिजी, आजकल की बीजी लाइफस्टाइल में इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि माइक्रोवेव हर किसी की पहली आवश्यकता बन गया है। आज माइक्रोवेव ने घंटों का काम कुछ मिनटों में करके लोगों के जीवन को बेहद सरल बना दिया है। बावजूद इसके कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए।

आने से बालों में ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है। इसकी नमी खो जाती है ऐसे में आप हेयर डिटॉक्स करके बालों में नमी सकते हैं।

कैसे करें हेयर डिटॉक्स

मुल्तानी मिट्टी

1। एक कटोरा में चार से पांच चम्मच मुलतानी मिट्टी लीजिए। इसके बाद इसमें दो से तीन चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। आखिर में दो चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। इसमें आप गुलाब जल भी मिल सकते हैं। अब आप पतला सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों में लगे और अच्छे से मसाज करते हुए बाल धोएं। आपको बता दें कि ईरानियन जर्नल आफ पब्लिक हेल्थ की एक रिसर्च के मुताबिक मुलतानी मिट्टी का इस्तेमाल

ऐसा करके न केवल आप अपने माइक्रोवेव को खराब कर सकते हैं बल्कि आपको सेहत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताते हैं 5 कौन सी चीजों को माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए...

फ़ोजन फ़रूट्स:- माइक्रोवेव में यदि आप फ़ोजन फ़रूट्स को डीफ़ॉस्ट करते हैं, तो ऐसा करने से वो खराब हो सकते हैं।

एल्युमिनियम फॉयल में खाना:-
एल्युमिनियम फॉयल में खाना रखकर गर्म करने से माइक्रोवेव में आग लगने का खतरा बना रहता है।

अंडा:-पूरे अंडे को कभी भी माइक्रोवेव

बालों को नेचुरली सॉफ्ट बनाने के साथ ग्रोथ में मदद करती है। ये आपके स्कैल्प को ठंडा रखने में मदद करता है। स्कैल्प पर जमी गंदगी को साफ करती है। वहीं सेब का सिरका एक माइल्ड एसिड होता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ केमिकल को निकालने में मदद करता है।

बेकिंग सोडा

2 से 3 कप गुनगुना पानी ले लीजिए। इसमें आधा कप बेकिंग सोडा डाल लीजिए और आधा नींबू निचोड़ लीजिए। इस अच्छे से मिक्स करके धीरे-धीरे अपने बालों पर डालें और हल्के हाथों से जड़ों में मसाज करें। कम से कम 10 मिनट ऐसा करने के बाद गुनगुने पानी के साथ शैंपू कर ले और कंडीशनर अप्लाई करें।

में रखने की गलती नहीं करनी चाहिए।
अंडे को छिलके सहित माइक्रोवेव में रखने
से उसमें तुरंत विस्फोट हो सकता है।

स्टायरोफोम कंटेनर:- स्टायरोफोम कंटेनर में खाना रखकर माइक्रोवेव में गर्म करने पर कंटेनर में उपस्थित रसायन का भोजन में मिल सकते हैं। जिसके कारण व्यक्ति को कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है।

फोजन मीट:- फोजन मीट को माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करने से वो अच्छी प्रकार से पकता नहीं है। ऐसा मीट कही से पका तो कहीं से कच्चा रह जाता है।

शब्द सामर्थ्य -054

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. आय व्यय का लेखा-जोखा, गणित, एकाउंट 3. विनती, अदब 6. दृष्टांत, सुपुर्दगी, उदाहरण 7. मूल्यवान, बहुमूल्य 8. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 10. बराबर, सम 12. मुख, चेहरा 14. अनुकृति, अनुकरण, असल का विलोम 17. दिमाग,

मस्तिष्क 18. मनोहर, सुंदर, इच्छित, प्यारा 19. गर्मी, ताप 21. रसिया, प्रेमी, रसपान करने वाला 23. दबाव, भार 24. भीख 25. काम से जी चुराने वाला, आलसी।

ऊपर से नीचे

1. साहस, वीरता, बहादुरी 2. बहिन, प्रवाहित होना 3. प्रणय क्रीडा, सुखोपभोग, हावभाव

4. विश्वास, प्रतीति 5. इंतजार 9. खाने-पीने का सामान, रसद 11. नशीला, मदभरा 12. घायल, जखमी 13. झुकना, प्रणाम, नमस्कार 14. दृष्टि, निगाह 15. तीव्रइच्छा 16. अर्थ, अभिप्राय, स्वार्थ 20. इम्तिहान, योग्यता आदि को परखना 22. जुल्म, अन्याय 23. पत्नी, बीवी, एक प्रत्यय।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 53 का हल

दा	ढ़ी		की		खा	सो	आ	म
वा		त	म	त्रा			जा	
न	जा	क	त		बा	अ	द	ब
ल		ली		वि	ला	प		हा
	अ	फ	सा	ना		मा	हि	र
दा	ब			श	गु	न		
न		उ	प	का	र		शि	
व		त्स		र		त	क	ला
	सा	व	न		गु	रु	वा	र

67वें बर्थडे पर नागार्जुन की 100वीं फिल्म किंग 100 की पहली झलक आउट!

नागार्जुन की 100वीं फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली एक्टर के 67वें जन्मदिन पर, मेकर्स ने फैंस को तोहफा देते हुए इस प्रोजेक्ट का टाइटल और पहली झलक दोनों ही ऑफिशियली जारी कर दी हैं. खास बात ये है कि नागार्जुन की ये फिल्म बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी से क्लैश करेगी. जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

नागार्जुन की 100वीं फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. वहीं एक्टर के 67वें जन्मदिन के मौके पर, मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक वाला वीडियो जारी किया और साथ ही इसका टाइटल और रिलीज डेट भी बता दी.

1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो की शुरुआत नागार्जुन की दमदार आवाज से होती है, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे समाज लोगों को उनकी दौलत के आधार पर परखता है. वे कहते हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्हें लूज़र कहा जाता था, लेकिन अमीर बनने के बाद उन्हें द किंग कहा जाने लगा.

नागार्जुन की 100वीं फिल्म टाइटल किंग 100 रखा गया है. टाइटल की झलक में नागार्जुन एक स्टाइलिश अवतार और दमदार शाही अंदाज में नजर आ रहे हैं. फिल्म में शानदार प्रोडक्शन वैल्यू का भी वादा किया गया है. गौरतलब है कि इस फिल्म के साथ रा कार्तिक तेलुगु फिल्मों में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे हैं. पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, किंग के लिए रास्ता बनाइए, वह अपने स्टाइल, स्वैग और करिश्मे के साथ राज करने आ गए हैं.

बता दें कि नागार्जुन की 100वीं फिल्म किंग 100 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं इसका बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग से क्लैश होगा. इन फिल्मों का मुकाबला देखने के लिए फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है.

तेलुगु फिल्म किंग 100 में 28 साल बाद नागार्जुन और तब्बू की जोड़ी फिर से पर्दे पर साथ नजर आएगी. दोनों ने पहली बार 1996 की तेलुगु फिल्म निन्ने पेन्नादथा में साथ काम किया था. इसके बाद उन्होंने आविदा मा आविडे (1998) और सिसिन्द्री (1999) में भी साथ काम किया था.

नागार्जुन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार लोकेश कनगराज की तमिल फिल्म कुली में नजर आए थे, जिसमें रजनीकांत, ररुति हासन और सौबिन शाहिर मुख्य भूमिकाओं में थे. यह फिल्म थिएटर में 14 अगस्त, 2025 को वॉ 2 के साथ रिलीज हुई थी. बाद में यह फिल्म 11 सितंबर, 2025 को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई थी.

लोकेश कनगराज की डीसी' 4 सितंबर से ओटीटी पर आ सकती है!

निर्देशक अरुण मथेश्वरन के निर्देशन में बनी अभिनेता लोकेश कनगराज की फिल्म डीसी' ने वर्ष 2026 में सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। फिल्म में लोकेश कनगराज ने देवदास' की मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ वामिका गब्बी और संजना कृष्णमूर्ति भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

फिल्म की कहानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की चर्चित कृति देवदास' से प्रेरित है। हालांकि, फिल्म में पारंपरिक प्रेम कहानी को अपराध, बदला, हिंसा और संघर्ष से जोड़ते हुए एक अलग अंदाज में पेश किया गया है। कहानी में देवदास का किरदार प्रेम और धोखे के बीच एक अपराधी की दुनिया में फंसता नजर आता है।

डीसी' को 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को इसकी अलग कहानी, दमदार एक्शन दृश्यों और अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत के लिए दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। फिल्म में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कालजयी कहानी को आधुनिक अपराध की दुनिया की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है।

फिल्म में देवदास का किरदार प्रेम, विश्वासघात और खतरे के बीच संघर्ष करता है। यही वजह है कि कहानी को पारंपरिक देवदास' से अलग और आधुनिक रूपांतरण के तौर पर देखा जा रहा है।

सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद अब फिल्म के डिजिटल प्रसारण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक, डीसी' 4 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो और सन एनएक्सटी पर प्रसारित हो सकती है। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण भी ओटीटी पर उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि, 4 सितंबर की तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी फिल्म के निर्माताओं या संबंधित डिजिटल मंचों की ओर से नहीं की गई है। इसलिए दर्शकों को फिलहाल इसे संभावित ओटीटी रिलीज तारीख के तौर पर ही देखना चाहिए।

डीसी' लोकेश कनगराज के करियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण फिल्म है। अब तक एक्शन फिल्मों के निर्देशन के लिए पहचाने जाने वाले लोकेश इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में नजर आए हैं।

फिल्म की व्यावसायिक सफलता ने उनके इस बदलाव को मजबूती दी है। वहीं, निर्देशक अरुण मथेश्वरन ने भी अपनी विशिष्ट और तीव्र कहानी कहने की शैली को फिल्म के माध्यम से आगे बढ़ाया है।

यदि ओटीटी रिलीज की तारीख की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो सिनेमाघरों में फिल्म नहीं देख पाए दर्शकों को देवदास की इस नए अंदाज वाली अपराध-कथा को घर बैठे देखने का मौका मिलेगा।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी की मासूम गीता से खाकी की दबंग नेता तक, हर रंग में माहिर हैं चित्रांगदा

हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों में जगह बना ली। चित्रांगदा सिंह भी ऐसी ही अभिनेत्री हैं। पर्दे पर उनकी मौजूदगी जितनी खूबसूरत लगती है, उनके किरदारों में उतनी ही गहराई भी दिखाई देती है। कभी उन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी में संवेदनशील और मासूम गीता बनकर दर्शकों का दिल जीता, तो कभी बाजार', बॉब बिस्वास और गैसलाइट जैसे प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग रंग दिखाए। हाल के वर्षों में खाकी- द बंगाल चैप्टर में एक प्रभावशाली राजनीतिक किरदार निभाकर उन्होंने फिर साबित किया कि वह सिर्फ ग्लैमर तक सीमित अभिनेत्री नहीं हैं। चित्रांगदा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1976 को हुआ था। उनका बचपन मेरठ, कोटा और बरेली जैसे शहरों में बीता। उनके पिता सेना में अधिकारी थे, इसलिए परिवार को अलग-अलग जगहों पर रहना पड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। धीरे-धीरे उन्हें विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में काम मिलने लगा। गुलजार के म्यूजिक वीडियो सनसेट प्वाइंट' में नजर आने के बाद उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उनके लिए फिल्मों का रास्ता खुला।

साल 2005 में निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से चित्रांगदा ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में उन्होंने गीता का किरदार निभाया था। कॉलेज की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका किरदार बेहद संवेदनशील था। चित्रांगदा ने इसे इतनी सहजता से निभाया कि दर्शकों और आलोचकों दोनों ने उनकी तारीफ की। पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड भी मिला।



लेकिन बॉलीवुड में पहली फिल्म की सफलता के बाद सब कुछ आसान नहीं रहा। उनकी अगली फिल्म कल- यस्टरडे एंड टुमारो उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। इसके बाद उन्होंने कुछ समय फिल्मों से दूरी बनाई। 2008 में सॉरी भाई!' से वापसी की, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद फिर एक ब्रेक आया।

फिर आया 2011, जिसने चित्रांगदा के करियर को एक नई दिशा दी। सुधीर मिश्रा की ये साली जिंदगी' में उन्होंने इरफान खान के साथ काम किया। क्लब सिंगर प्रीति के किरदार में उनका अंदाज काफी अलग था। इसी साल वह अक्षय कुमार के साथ देसी बॉयज' में भी नजर आईं। यहां उनका किरदार ग्लैमरस था और फिल्म ने उन्हें बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया।

इसके बाद चित्रांगदा ने लगातार अलग-अलग तरह के किरदार आजमाए। इंकार में उन्होंने महत्वाकांक्षी माया का किरदार निभाया, जबकि आई, मी और मैं में वह करियर को लेकर गंभीर महिला के रूप में नजर आईं। उन्होंने खुद को किसी एक तरह के किरदार में बांधकर नहीं रखा। कभी वह स्पेशल अपीयरेंस में दिखीं, तो

कभी डांस नंबर का हिस्सा बनीं।

साल 2018 उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव लेकर आया। उन्होंने सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय ही नहीं किया, बल्कि सूरमा' के जरिए निर्माता के तौर पर भी कदम रखा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की जिंदगी पर बनी इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसी साल वह साहेब, बीवी और गैंगस्टर 3' में भी नजर आईं।

इसके बाद चित्रांगदा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख किया। 2022 में वह मॉडर्न लव मुंबई' में नजर आईं। 2021 की फिल्म बॉब बिस्वास' में उन्होंने मेरी बिस्वास का किरदार निभाया। यह भूमिका भी उनके पहले के ग्लैमरस किरदारों से काफी अलग थी। 2023 में गैसलाइट' में उन्होंने रुक्मिणी का किरदार निभाया, जिसमें रहस्य और भावनाओं की कई परतें थीं। 2025 में आई खाकी- द बंगाल चैप्टर' में चित्रांगदा ने एक प्रभावशाली राजनीतिक किरदार निभाया। इस भूमिका में उनका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। पर्दे पर उनका आत्मविश्वास और राजनीतिक तेवर चर्चा में रहे।

भावना पानी ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की इच्छा जताई, कहा- उनके जैसा कोई नहीं



अभिनेत्री भावना पानी फिल्मों और रंगमंच में खास पहचान रखती हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने करियर में एक बार संजय लीला भंसाली की फिल्मों में काम करना चाहती हैं। उन्होंने बताया, संजय लीला भंसाली सर, चाहे मुझे कोई भी रोल दें, उसे आगे ले जाना मेरे ऊपर है। मैं उम्मीद

करती हूं कि जब भी मुझे उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, तो वह शानदार, दमदार और चुनौतीपूर्ण रोल होगा। मैं यह भी उम्मीद करती हूं कि वह डांस वाला हो क्योंकि मैंने बचपन से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखा है। मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली सर को शास्त्रीय संगीत

और नृत्य की अच्छी समझ भी है। अभिनेत्री का मानना है कि हिंदी फिल्मों में अगर किसी निर्देशक ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और म्यूजिक को बड़े कैनवास पर उतारा है, तो वे संजय लीला भंसाली सर हैं।

अभिनेत्री ने कहा इमोशन कभी भी बिना तर्क के नहीं आते हैं। ये आते कहां से हैं, उसका मकसद और जरूरत क्या है? यह सब समझने के लिए बहुत सारे तर्क और विज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको बिहेवियरल साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए। कई ऐसी चीजें हैं जहां आपके दिमाग का तार्किक होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि तार्किक दिमाग के साथ-साथ कल्पना और भावना की भी जरूरत होती है। वैज्ञानिक सोच होने से एक एक्टर को बहुत मदद मिलती है।

अभिनेत्री भावना पानी हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने नौकरानी रागिनी का किरदार निभाया था। अभिनेत्री ने इस फिल्म के लोकप्रिय गाने ओ सुंदरी में अपने डांस से वह काफी चर्चा में आई थीं।

चमोली (आरएनएस)। तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोनीगाड़ गंदरा उफान पर होने से ग्राम सभा खाटली के किमाणा गांव के ठीक नीचे भू-धंसाव हो रहा है और गांव में दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं कृषि भूमि का भी कटाव हो रहा है। किमाणा गांव में कमल सिंह और नारायण सिंह की दो गोशालाएं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं जबकि सुंदर सिंह व भागीरथी देवी की गोशालाओं को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, नारायण सिंह का शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं राजेंद्र सिंह के मकान पर मोटी दरारें आ जाने से उनका घर कभी भी ढह सकता है। पूर्व प्रधान प्रमिला पवार, महिला मंगल दल अध्यक्ष कविता देवी, जयेंद्र सिंह, अजय सिंह और सुरबीर सिंह ने बताया कि गांव में लगातार बने खतरे के कारण 70 परिवार दहशत के साये में जीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 की आपदा के बाद और शनिवार रात हुई भारी बारिश के कारण लोनीगाड़ गंदरा उफान पर है जिससे गांव के ठीक नीचे लगातार कटाव हो रहा है। घटना की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन की टीम ने ग्राम किमाणा का निरीक्षण किया। प्रभारी आरके यतेंद्र राणा और राजस्व उपनिरीक्षक प्रदीप कपरवान ने बताया कि गांव में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासनिक टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए है।

सू- दोकू क्र.054

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

- कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
- बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.53का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

मोदी मॉडल में 'सत्ता' से ज्यादा 'सेवा' का दावा

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। भाजपा नेताओं की ओर से बार-बार दोहराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कभी शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं रही, बल्कि जनसेवा का अवसर है। यह दावा ऐसे समय में सामने आ रहा है जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ संगठन को सक्रिय कर रही है।

भाजपा की राजनीति में सेवा को केंद्रीय विचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सत्ता का अर्थ केवल सरकार चलाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। यही वजह है कि भाजपा अपने राजनीतिक अभियान में विकास के साथ गरीब कल्याण, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण को प्रमुखता दे रही है।

भाजपा नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में सत्ता की परिभाषा को बदलने का प्रयास किया है। उनके लिए सरकार का मतलब केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान और जरूरतमंद तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। भाजपा इस सोच को जनधन, आवास, शौचालय, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और डिजिटल सेवाओं जैसी योजनाओं से जोड़कर पेश करती है। पार्टी का तर्क है कि शासन की सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि उसका लाभ समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जो लंबे समय तक व्यवस्था से दूर रहा।

हालांकि उत्तराखंड में भाजपा के सामने इस दावे को जमीन पर साबित करने की



- ◆ भाजपा के लिए सत्ता शक्ति नहीं, सेवा का है माध्यम
- ◆ प्रदेश में जनसेवा के सदेश के साथ 2027 की तैयारी
- ◆ संगठन का दावा समाज और राष्ट्र सेवा का है साधन

बड़ी चुनौती है। पहाड़ी जिलों में आज भी पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, सड़क, आपदा और स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार अपनी जगह है, लेकिन पहाड़ का मतदाता यह भी जानना चाहता है कि उसके गांव में रोजगार कब पहुंचेगा, अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक कब उपलब्ध होंगे, सड़कें कब सुरक्षित होंगी और आपदा के समय सरकारी तंत्र कितनी तेजी से उसके साथ खड़ा होगा। यानी भाजपा के लिए सेवा का दावा अब केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि 2027 में जनता की कसौटी भी बनने वाला है।

भाजपा संगठन लगातार बूथ स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। पार्टी की रणनीति में कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं

को संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं का मानना है कि पार्टी की असली ताकत उसका कैडर और कार्यकर्ता है। इसलिए सत्ता में रहते हुए भी संगठन को जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

भाजपा के सेवा वाले नैरेटिव ने विपक्ष के सामने भी चुनौती खड़ी की है। कांग्रेस लगातार सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में आगामी चुनाव में मुकाबला केवल भाजपा की उपलब्धियों बनाम विपक्ष के आरोपों का नहीं होगा, बल्कि दोनों पक्षों को यह साबित करना होगा कि वह उत्तराखंड की जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव कैसे ला सकते हैं। भाजपा जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों और धामी सरकार के कामकाज को जनसेवा के माडल के रूप में पेश करेगी, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भर्ती और आपदा जैसे मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम बताना भारतीय लोकतंत्र में नया विचार नहीं है। लगभग हर राजनीतिक दल जनता की सेवा को अपना लक्ष्य बताता है। असली सवाल यह है कि सत्ता में आने के बाद उस विचार का कितना हिस्सा जमीन पर दिखाई देता है। उत्तराखंड में 2027 का चुनाव इसी दावे की परीक्षा बन सकता है। भाजपा यदि लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर चल रही है तो उसे जनता के सामने यह भी साबित करना होगा कि उसके लिए सत्ता वास्तव में सेवा का माध्यम है। क्योंकि चुनावी भाषण में सत्ता सेवा हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में उसकी अंतिम परीक्षा जनता के अनुभव से होती है।

पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र बहाल करने की मांग दोहराई!

अल्मोड़ा (आरएनएस)। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की जिला इकाई ने रैमजे इंटर कॉलेज सभागार में आयोजित बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को शीघ्र बहाल करने की मांग दोहराई। बैठक में सरकारी विभागों और सार्वजनिक सेवाओं में बढ़ते निजीकरण पर भी चिंता जताते हुए इसका विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बैठक को संबोधित करते हुए एनएमओपीएस के जिलाध्यक्ष गणेश भण्डारी ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) और यूनिकाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) कर्मचारियों को वह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा नहीं दे सकती, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था में उपलब्ध थी। उन्होंने सभी शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि देशभर के लाखों शिक्षक-कर्मचारियों के भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सार्वजनिक सेवाओं के बढ़ते निजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने के बजाय उन्हें संसाधनों से

सशक्त बनाकर नियमित नियुक्तियों की जानी चाहिए। जिला संरक्षक डॉ. मनोज कुमार जोशी ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसे बहाल कराने के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। प्रांतीय कोर कमेट्री सदस्य डॉ. धीरेंद्र पाठक ने वर्तमान पेंशन व्यवस्था को कर्मचारियों के भविष्य के लिए असुरक्षित बताते हुए आंदोलन को और तेज करने की आवश्यकता बताई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पंकज पांडेय ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की न्यायसंगत मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों की लगातार अनदेखी की गई तो कर्मचारी लोकतांत्रिक एवं चरणबद्ध आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला ने भी पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग का समर्थन किया। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी नितेश काण्डपाल, धौलादेवी ब्लॉक संयोजक जीवन साह, रमेश दानू, बसन्त पाण्डेय, महेश आर्या, दिनेश तिवारी, डीके जोशी, संजय जोशी, गिरिजा भूषण जोशी, महताब अंसारी, राजू लटवाल, रमेश महारा, तारा बिष्ट, अशोक रावत सहित विभिन्न शिक्षक एवं कर्मचारी

संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय अभियान को समर्थन देते हुए आंदोलन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

बरसात से लिंक मार्गों में बने गड्ढे, जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी

रुद्रपुर(आरएनएस)। बरसात के कारण रुद्रपुर रोड समेत क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर गड़ब हो गए हैं। इनमें बारिश का पानी भरने से सड़क पर आवागमन मुश्किल हो गया है। जलभराव के कारण गड़ब दिखाई नहीं देने से दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। डीडी चौक से आदित्य चौक की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, नमक फैक्ट्री रोड समेत शहर के कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से लोगों को पेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात शुरू होने के बाद सड़कों की स्थिति और खराब हो गई है। कई स्थानों पर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि आवागमन सुचारु हो सके और हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।

बारिश के बीच श्रद्धा से मनाया सिंधी समाज का पावन तीजड़ी पर्व



संवाददाता

देहरादून। सिंधी समाज का पावन तीजड़ी पर्व झूलेलाल मनोकामना सिद्ध मंदिर में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया।

आज यहां सिंधी समाज का पावन तीजड़ी पर्व झूलेलाल मनोकामना सिद्ध मंदिर में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज की सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना को लेकर 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा। पर्व के अवसर पर समाज की महिलाएं मंदिर में एकत्र हुईं और विधि-विधान से तीजड़ी माता की पूजा-अर्चना की। इसके बाद श्रद्धापूर्वक तीजड़ी माता की कथा सुनी गई। महिलाओं ने परिवार की खुशहाली, पति की दीर्घायु और दांपत्य जीवन में सुख-शांति की प्रार्थना की।

तीजड़ी पर्व पर चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। परंपरा के अनुसार व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रमा के दर्शन एवं पूजा-अर्चना के बाद ही अपना निर्जला व्रत खोलती हैं। हालांकि, बारिश और घने बादलों के कारण चंद्रमा के दर्शन नहीं हो सके। इसके बावजूद महिलाओं की श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने भले ही चंद्रमा को बादलों के पीछे छिपा दिया हो, लेकिन परिवार की खुशियों और पति की दीर्घायु के लिए उनके मन में आस्था का चांद सदैव जगमगाता रहेगा। पर्व के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना रहा।

महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना कर परिवारों में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर माया चंदानी, मीना माधवानी, भावना सिंधी, युविका, आयुषी चिचडा, रिद्धि, तुलिका, लविशा, आन्या, अर्चना पाहवा, काजल, दिव्या, मधु कुंदनानी, कोमल, अंजलि अगिचा, भावना, सीमा खत्री, नेहा चावला, सुहानी अरोड़ा, शालिनी छाबड़ा, आयुषी छाबड़ा, एकता अगीचा, विशाखा अगीचा सहित समाज की अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं।

‘राज्य के झीलों का इसरो के सहयोग से सैटेलाइट मैपिंग कर चेतावनी सूचक उपकरणों को तत्काल लगाने की मांग’

संवाददाता

देहरादून। संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा मुख्यसचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों में ये मांग करते हुए बताया गया है की जनपद पिथौरागढ़, भारत-नेपाल सीमा पर विगत समय में ग्लेशियरों में नई झीलें चिन्हित हुई हैं जो कमजोर चट्टानों व मलबे के मोराइन बाँध से बनी हैं जिन्होंने वॉटर बम का रूप ले लिया है। तेज बारिश, भूस्खलन, हिमस्खलन या ग्लेशियर का हिस्सा गिरने पर इनके फूटने की संभावना है जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकती है। संगठन उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र भट्ट ने लिखा है की एनडीएम द्वारा इन क्षेत्रों में 13 झीलों अत्यंत संवेदनशील मानी गई हैं इसलिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। भेजे गए सुझावों में लिखा गया है की भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील दून सहित पहाड़ी क्षेत्र जोन 4 और 5 की खतरनाक श्रेणी में है। यहां प्रस्तावित 500 भूकंप चेतावनी प्रणाली में से अब तक आधे ही लगे हैं।नेपाल-हिमाचल सीमा के थ्रस्ट एरिया में सभी जगह इस योजना को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। मौसम चेतावनी के लिए ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन समेत दून, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली में प्रस्तावित डॉप्लर रडार लगाने समेत मल्टी-हैजर्ड सायरन सिस्टम, जीएसआई से सम्बद्ध भूस्खलन अलर्टी वार्निंग लगाने के कार्य भी युद्धस्तर पर किए जाएँ। सभी झीलों का इसरो के सहयोग से सैटेलाइट मैपिंग कर जोखिम श्रेणीकरण किया जाए।

राष्ट्रीय फलक पर गूँजा ‘शुद्धिकरण’ विवाद ◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता के सामने सवाल इससे बड़ा है। क्या चुनाव की राजनीति बेरोजगार युवा को रोजगार देगी? क्या पहाड़ से पलायन रोकने का रोडमैप सामने आएगा? क्या आपदा प्रभावित गांवों को सुरक्षित बनाने की ठोस योजना बनेगी? क्या स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्थाओं पर कोई दल स्पष्ट जवाब देगा? यही वह सवाल हैं जिनसे कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक बच नहीं सकता।

भाजपा कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताकर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पलटकर भाजपा पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। दोनों दलों की सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। लेकिन 2०27 के चुनाव में अंतिम फैसला नेताओं के बयानों से नहीं, मतदाता के सवालों से होगा। उत्तराखंड का मतदाता यह देखेगा कि कौन दल भावनाओं की राजनीति से आगे बढ़कर रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जमीन और आपदा जैसे सवालों पर ठोस जवाब देता है। क्योंकि चुनाव में मुद्दा वही नहीं होता जो राजनीतिक दल तय करें।मुद्दा वह भी होता है जिसे जनता अपने जीवन में रोज झेलती है।

खटीमा में नगर वन ऑक्सीजन पार्क का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

संवाददाता

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नवनिर्मित नगर वन ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नवनिर्मित नगर वन ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर में पौधरोपण करने के साथ ही पार्क का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खटीमा क्षेत्र के विकास से संबंधित छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने नगर वन ऑक्सीजन पार्क का विस्तारीकरण करने, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय को पार्क परिसर में स्थानांतरित करने, खटीमा में स्टेडियम का निर्माण करने, क्रियाशाला का निर्माण करने, सर्किट हाउस का निर्माण करने तथा वैंडिंग जोन विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा की भौगोलिक स्थिति पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्यास वैली, पंचाचूली और आदि कैलाश की ओर जाने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खटीमा में सर्किट हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने नगर वन ऑक्सीजन पार्क के विस्तारीकरण एवं आवश्यक संसाधनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर वन ऑक्सीजन पार्क के निर्माण से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होगा। पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक शौचालय बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक तापवृद्धि



और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच वनों और पर्यावरण का महत्व और अधिक बढ़ गया है। विकास और पर्यावरण अर्थात इकोलॉजी और इकोनॉमी एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोजगार और आजीविका के स्थायी अवसर सृजित किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है।

नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने नगर वन ऑक्सीजन पार्क के विस्तारीकरण तथा जीर्ण-शीर्ण वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय को पार्क परिसर में स्थानांतरित कर नए कार्यालय के निर्माण का अनुरोध किया। उन्होंने खटीमा में नगर वन ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरिता राणा, दर्जाधारी राज्य मंत्री श्रीमती मोहिनी पोखरिया, गंभीर सिंह धामी, डॉ. अनिल कपूर ‘डब्लू’, किशन सिंह किन्ना, रणजीत सिंह नामधारी, आयोग के सदस्य डॉ. जेड. ए. वारसी, गुड्डू टम्टा, पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा, रणदीप पोखरिया, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, वन संरक्षक नीतिशमणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह, यू.सी. तिवारी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज व हनी प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं: वर्द्धन

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज एवं हनी प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में नीति आयोग के सदस्यों प्रो. एम. श्रीनिवास एवं प्रो. के.वी. राजू सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाओं, नवाचार, रोजगार सृजन तथा राज्य के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज एवं हनी प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक, बेहतर मार्केट लिंकेज एवं वैल्यू एडिशन के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि को बढ़ावा देने तथा



इसके माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नीति आयोग से विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट प्रोपोजल रिपोर्ट (पीपीआर) फॉर्मैट्स साझा किए जाने एवं उनके अधिक उपयोगी एवं परिणाम आधारित बनाने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं का बेहतर उपयोग करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर की चुनौतियों का प्रभावी समाधान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का अध्ययन कर उन्हें राज्य की नीतियों एवं कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाएगा। वरि. सदस्य नीति आयोग प्रो. एम. श्रीनिवास स्वास्थ्य क्षेत्र में आभा आईडी की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे सैचुरेट करने पर भी जोर दिया

गया। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को मजबूत करने से नागरिकों को बेहतर एवं निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वरि. सदस्य नीति आयोग प्रो. के.वी. राजू ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन को कौशलयुक्त बनाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन ऐप एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों को आवश्यक कौशल प्रदान करने तथा उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। बैठक में एरोमा सेक्टर में इंडस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने, उत्पादन को बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ने तथा उत्पादों की प्रेडिंग एवं ट्रेसेबिलिटी की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। राज्य में इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों एवं भविष्य की संभावनाओं से नीति आयोग के सदस्यों को अवगत कराया गया।

राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से मिला उत्तराखण्ड: धामी



संवाददाता

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से उत्तराखण्ड मिला है। आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने खटीमा गोलीकांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज

का दिन उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानन्द भट्ट और परमजीत सिंह को स्मरण करने का दिन है। उत्तराखण्ड का प्रत्येक नागरिक इन वीर सपूतों के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। राज्य आंदोलन से जुड़े अपने अनुभवों को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा गोलीकांड ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य के लिए चल रहे आंदोलन को नई दिशा दी और लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हम सभी मिलकर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का निर्माण करें,

यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा की धरती राज्य आंदोलन की तपोभूमि है। यदि इसे उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन की जननी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा “उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023” लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये की गई है। राज्य आंदोलन के दौरान घायल एवं जेल गए आंदोलनकारियों को 7 हजार रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 5500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी

चोरी के ट्रक सहित दो लोग गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। चोरी हुए ट्रक मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके कब्जे से चुराया गया ट्रक बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती शाम कोतवाली श्यामपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 35 लाख रुपये कीमत के चोरी हुए 12 टायरा ट्रक को मुकदमा लिखे जाने के मात्र 48 घंटे के भीतर बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बीती 24 अगस्त को कोतवाली श्यामपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित माईनिंग चेक पोस्ट से उक्त ट्रक चोरी किया गया था। घटना के संबंध में कोतवाली श्यामपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पड़ताल में जुटी कोतवाली श्यामपुर पुलिस ने प्रकाश में आए दो संदिग्ध को गिरफ्तार कर विवेचना एवं



पूछताछ की तो आरोपियों ने ट्रक चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने ट्रक को गैण्डीखाता क्षेत्र में जंगल गुजर बस्ती की ओर छिपाकर रखा है। जिस पर पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को साथ लेकर बरामदगी के लिए मौके पर पहुंची तथा उनकी निशानदेही पर गुजर बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते के पास जंगली झाड़ियों के समीप से एक लाल रंग का ओपन बॉडी 12 टायरा ट्रक बरामद किया। आरोपियों ने ट्रक की पहचान छिपाने के लिए उस पर लगी नंबर प्लेट भी हटा दी थी। बहरहाल पुलिस ने उन्हे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शहजाद परवेज पुत्र अमीनुद्दीन निवासी मोहल्ला मुगलुशाह थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश व हबीब खाँ पुत्र प्यारे खाँ, निवासी मोहल्ला किला, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। बरामद ट्रक की कीमत 35 लाख रुपये आंकी गयी है।

25 लाख रुपये की ड्रग्स सहित तीन लोग गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

देहरादून। नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनके कब्जे से लगभग 25 लाख रुपये तक की एमडीएमए बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि बीते

रोज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोतवाली टनकपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी की एक सूचना के बाद क्षेत्र में संयुक्त चैकिंग अभियान



चलाया गया। इस दौरान बाइक सवार तीन संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 244.06 ग्राम एमडीएमए बरामद की गयी। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपये आंकी गई है। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स यूनिट द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज की गहनता से जानकारी की जा रही है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। गिरफ्तार हुए नशा तस्करों के नाम इमरान, निवासी रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर, आशीष, निवासी रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर व अभिषेक, निवासी रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर बताये जा रहे हैं।

‘राहुल गांधी पर एफआईआर तत्काल वापस लो’

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों के संघर्ष और प्रयासों से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और सामाजिक एकजुटता की मजबूत नींव तैयार की है। आज जब सभी समाज के लोग साथ बैठकर, साथ खाकर और एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के कार्यक्रम के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ जैसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और समाज को बांटने वाली मानसिकता का प्रतीक है। इस घटना से पूरे समाज में रोष है। ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय दलितों,



खड्गे का अपमान करने वालों पर तत्काल मुकदमा दर्ज करो: थापर

वंचितों और गरीबों की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई।

अभिनव थापर ने कहा कि हल्लानी के जिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसी थाने में इस प्रकरण को लेकर 18 तारीख से शिकायत लंबित है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह दोहरा रवैया कई गंभीर सवाल खड़े करता है

और भाजपा की समाज को बांटने वाली मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ कानूनी, लोकतांत्रिक और सड़क तीनों स्तरों पर मजबूती से संघर्ष करेगी।

अभिनव थापर ने स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर तत्काल वापस ली जाए। साथ ही, रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड्गे के कार्यक्रम के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ का आयोजन कर उनका अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ उपलब्ध विडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए तथा पूरे प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 264 वाहनों का चालान

संवाददाता

टिहरी। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 264 वाहनों का चालान कर एक लाख 14 हजार 400 रुपये का संयोजक शुल्क वसूल किया।

आज यहां जनपद टिहरी गढ़वाल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु जनपद के सभी थाना क्षेत्रों एवं यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चैकिंग अभियान चलाया गया।

सघन चैकिंग अभियान के दौरान

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 264 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 1,14,400 रुपये संयोजन शुल्क वसूल किया गया। 61 वाहन चालकों के चालान

कुल 1,14,400 का संयोजन शुल्क वसूला

माननीय न्यायालय प्रेषित किए गए जिसमें 5 सीज किए गए वाहन शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए



हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि सड़क सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा नशे में वाहन चलाने, तेज गति, लापरवाही एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

टिहरी पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट/सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, निधिरित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा नशे की हालत में कभी भी वाहन न चलाएं। स्वयं सुरक्षित रहें और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।